सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान से बिहार में विकास को नयी उड़ान

पटना (आससे)। बिहार में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत बड़े पैमाने पर मरम्मत, अनुरक्षण एवं नव निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के 38 जिलों में कुल 1,03,445 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन कार्यों की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों को सौंपते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने 17 सितंबर 2026 से शुरू किए गए इस अभियान के माध्यम से पहले से मौजूद सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण और रखरखाव के साथ-साथ नई जनोपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण की व्यापक पहल की है।

बिहार सरकार

विद्युत कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

विद्युत भवन प्रमण्डल, मोतिहारी, भवन निर्माण विभाग

ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–14/2026–27

(Double Bid System)

(केवल ई–निविदा पद्धति बेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू. में)	अग्रधन की राशि (रू. में)	निविदा कागजात का मूल्य (रू० में) (अप्रत्यर्पणीय)	ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क (रू०)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Estimate for Renovation of E/W & E/I in OBC Boys Hostel at Ambika Nagar, Motihari, Distt- East Champaran.	44,21,168.00	88,500.00	5,000.00	As per Online requirement	01 माह

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमण्डल, मोतिहारी।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक–27.10.2026 बेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की तिथि एवं समय : दि0–09.11.2026 से दि0–29.11.2026 तक 3:00 अपराह्न तक। केवल बेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
4. निविदा कागजात अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक–30.11.2026 के 3:00 बजे तक केवल बेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
5. निविदा तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक–01.12.2026 को 3:30 बजे। केवल बेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर
6. निविदा वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी से तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात्।
7. प्री–बीड मीटिंग की तिथि एवं समय : दिनांक–18.11.2026 को विद्युत अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, विद्युत भवन अंचल, उत्तर बिहार, भवन निर्माण विभाग, पटना। (3:00 बजे अपराह्न)
8. निविदा की वैधता की अवधि : 120 दिन।
9. निविदा स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता : सक्षम पदाधिकारी।

निविदा की विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar एवं www.eproc2.bihar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

विद्युत कार्यपालक अभियंता,
विद्युत भवन प्रमण्डल, मोतिहारी
भवन निर्माण विभाग।

PR- 014494 (BCD) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल बक्सर

ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 03/2026-27

(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

कार्यों की विवरणी (योजना/शीर्ष/मद का नाम) : – सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण कार्य अन्तर्गत।

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रूपये में)	अग्रधन की राशि (लाख रूपये में)	परिमाण – विपत्र का मूल्य (केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान किया जाना है) (अप्रत्यर्पणीय) (रूपये में)	बीड प्रोसेसिंग शुल्क (केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान किया जाना है) (अप्रत्यर्पणीय) (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)
01	02	03	04	05	06	07
1	केसठ प्रखंड अन्तर्गत पंचायत रामपुर के बुड़ावास महादलित टोला में सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड का निर्माण कार्य। (मौजा – रामपुर, थाना नं0 329, खाता संख्या – 243, खेसरा संख्या – 595/1075, रकबा 12 डी0)	29.65000	0.59300	5000.00	590.00 Or as per online mode	6 माह

2- विज्ञापन निर्गत करने की तिथि : दिनांक –27-10-2026
3- निविदा कागजात अपलोड करने की प्रारम्भीक तिथि एवं समय : दिनांक 19-11-2026 को 10.00 बजे पुर्वाह्न से (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4- निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 24-11-2026 समय 3.00 बजे अपराह्न । (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
5- तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 26-11-2026 समय 11.30 बजे पूर्वाह्न (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6- वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में सूचित किया जायेगा। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7- निविदा खोलने का स्थान : सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर
8- निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
9- विज्ञापनदाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्ड़ल बक्सर।

निविदा की विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल बक्सर।

PR- 014493 (Planning) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

बिहार सरकार

कार्यालय नगर पंचायत, पातेपुर

अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना

(ई–टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)

संख्या E-Tender - 08/2026–27

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता – नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पातेपुर।
2. निविदा आमत्रण सूचना निर्गत की तिथि – दिनांक – 03.11.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि – दिनांक – 12.11.2026 को 10:30 बजे से (On website www.eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बीड मीटिग का समय स्थान/तिथि – दिनाक – 13.11.2026 को समय 11:00 बजे पूर्वाहन से Offline स्थान –कार्यालय कक्ष, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पातेपुर।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय – दिनांक – 28.11.2026 के 15:30 बजे तक। (On website www.eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी एवं वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय – दिनांक– 30.11.2026 के 15:30 बजे तक
7. कार्य का विवरण :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य ((Through online payment) अप्रत्यर्पणीय रू0 में)	Bid Processing Fee(Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्क्लुसिडिंग मोनसून अवधि माह में)
1	2	3	4	5	6	7
A	वार्ड सं0–13 में मुकेश चौधरी के निवास से नगर पंचायत गेट तक जल वितरण नेटवर्क एवं 70 घरेलू कनेक्शन का कार्य।	6,46,600.00	13000.00	1250.00	590.00	02 माह
B	वार्ड सं0–11 में शिवनाथ राय के घर से पूनित भगत के घर, नसिबि राय के घर से बटेश्वर राय के घर तक और रामनाथ राय घर से मुन्ना राय के घर तक जल वितरण नेटवर्क एवं 100 घरेलू कनेक्शन का कार्य।	7,75,600.00	15600.00	1250.00	590.00	02 माह
C	वार्ड सं0–12 में कोआही चौक से डुमरा बोडर तक जल वितरण नेटवर्क एवं 170 घरेलू कनेक्शन का कार्य।	12,03,300.00	24100.00	2500.00	590.00	03 माह
D	वार्ड सं0–06 में पातेपुर बाजार से मौजे सहनी चौक से फकीरचन्द्र चौक और हनुमान चौक से मौजे सहनी चौक तक जल वितरण नेटवर्क एवं 150 घरेलू कनेक्शन का कार्य।	34,01,700.00	68100.00	5000.00	590.00	03 माह
E	वार्ड सं0–06 में फकीरचन्द्र चौक पी .सी.सी. सड़क के दोनो तरफ फर्लैक में पेवर ब्लॉक निमार्ण कार्य।	16,57,900,00	33,200.00	5000.00	590.00	03 माह
F	वार्ड सं0–14 में मो0 जमशेद के घर से अब्दूल सत्तार के घर तक ह्युम पाईप नाला निर्माण कार्य।	5,53,900.00	11100.00	1250.00	590.00	02 माह
G	वार्ड सं0–13 में बलदेव मांझी के घर से अशोक गोसाई के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	4,62,100.00	9300.00	750.00	590.00	03 माह

8. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
9. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in में देखा जा सकता हैं।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, पातेपुर

PR- 014506 (B & C) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

एलएनएमआई में स्टार्टअप-बैंक कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित

पटना (आससे)। राज्य के नवोदित उद्यमियों और प्रबंधन के छात्रों के लिए गुरुवार को स्टार्टअप-बैंक कनेक्ट-स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन पटना स्थित ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (एलएनएमआई) के स्टार्टअप सेल एवं उद्योग विभाग के सहयोग से हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप बिहार नीति, बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना रहा, जिसमें एलएनएमआई के लगभग 100 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ऋतु नारायण ने विद्यार्थियों में नवाचार की भावना विकसित करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से अपने विचारों को सफल व्यवसाय में बदलने का आह्वान किया। पटना जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक अतुल कुमार ने बिहार सरकार



की स्टार्टअप नीति के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने व्यावसायिक विचारों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इंडियन बैंक, एलएनएमआई के प्रबंधक पंकज कुमार ने स्टार्टअप की यात्रा में वित्तीय प्रबंधन, पूंजी की उपलब्धता और उचित वित्तीय योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बैंक ऋण, वित्तीय सहायता के विकल्पों, सरकारी योजनाओं, आवश्यक दस्तावेजों और व्यवसाय योजना की उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया। मौके पर सफल स्टार्टअप उद्यमियों ने अपनी स्टार्टअप यात्रा, चुनौतियों, नवाचार, बाजार की आवश्यकताओं और उद्यम स्थापना के दौरान मिली सीख को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। इस मौके पर स्टार्टअप की सफलता में वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग, संस्थागत सहयोग और बाजार तक जरूरी पहुंच पर जोर दिया गया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मेहदी 3 नवंबर को इस्तीफा देने पर अड़े

नयी दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने एक बार फिर दोहराया है कि वह 3 नवंबर को पार्टी और लोकसभा दोनों से इस्तीफा दे देंगे। यह तारीख उनके पिता, दिवंगत वरिष्ठ शिया धर्मगुरु आगा सैयद मेहदी की शहादत की बरसी के दिन ही पड़ रही है। आगा ने कहा कि जब से उन्होंने यह घोषणा की है, तब से उनके फैसले में कोई बदलाव नहीं आया है।

रुहुल्लाह ने कहा, मैं अपनी घोषणा के समय जितना पक्का था, आज भी उतना ही पक्का हूं। तब से कुछ भी नहीं बदला है। हालात वैसे ही हैं। मुझे अपना फैसला बदलने की कोई वजह नहीं दिखती। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था मैं 3 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और संसद, दोनों से इस्तीफा दे रहा हूं। आगे की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, देखते हैं कि उसके बाद हालात कैसे मोड़ लेते हैं।

अपने फैसले के बारे में बताते हुए सांसद रुहुल्लाह ने कहा कि पिछले दो वर्षों में पार्टी के बर्ताव ने उनके लिए यह जरूरी कर दिया है कि वह अपने राजनीतिक संघर्ष को और अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा, पिछले दो वर्षों में पार्टी ने जिस तरह का व्यवहार किया है और जिस तरह से उन्होंने मेरी राजनीतिक जिम्मेदारियों और हमारे साझा एजेंडे को लेकर किए गए मेरे प्रयासों को बदनाम करने की कोशिश की है। उसके बाद पार्टी में बने रहने का कोई मतलब नहीं है।

रेलवे पेंशनरों को बड़ी राहत, अब घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

पटना (आससे)।रेलवे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। अब जीवन प्रमाण.पत्र जमा करने के लिए हर साल बैंक जाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पूर्व मध्य रेल की ओर से 1 से 30 नवंबर 2026 तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 5.0 चलाया जाएगा। इसके तहत पेंशनभोगी ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण.पत्र जमा कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाना है। इससे विशेष रूप से बुजुर्ग और वरिष्ठ पेंशनरों को लाभ मिलेगा। 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों के लिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ही पोर्टल पर डिजिटल जीवन प्रमाण.पत्र जमा करने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए पेंशनरों को गूगल प्ले स्टोर से यूआईडीएआई का एप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एप इंस्टॉल करना होगा। दोनों एप इंस्टॉल होने के बाद ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर डिजिटल जीवन प्रमाण.पत्र तैयार किया जा सकता है।

बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती

15 दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन पर कारवाई के निर्देश

पटना (आससे)। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी की है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा से जुड़े निर्देशों की समीक्षा करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की अनुशंसाओं पर 15 दिनों के भीतर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान तेज किया जाए और निलंबित या रद्द लाइसेंस के बावजूद वाहन चलाते पकड़े जाने पर संबंधित वाहन जब्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गुरुवार को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में लीड एजेंसी, बिहा सड़क सुरक्षा परिषद की कार्यपालक समिति की बैठक हुई। इसमें सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, वाहन चालकों के प्रशिक्षण, स्कूली वाहनों की सुरक्षा, दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधार और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की समीक्षा की गई।

बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े आधारभूत ढांचे की प्रगति की समीक्षा की गई। पथ निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसारएराज्य में 5124 जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण या दोबारा पेंटिंग का कार्य पूरा किया गया है। इसके अलावा 161 स्थानों पर काम चल रहा हैए जबकि 1ए060 स्थानों पर कार्य प्रस्तावित है। वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 474 व्हीकल अंडरपास ;वीयूपीद्ध बनाए जा चुके हैं। 219 पर निर्माण कार्य जारी है और 11 प्रस्तावित हैं। वहींए 170 पैदल यात्री अंडरपास ;पीयूपीद्ध का निर्माण पूरा हो चुका है।

गंगा जल संधि पर आज पटना में सेमिनार बिहार की जल सुरक्षा पर होगा मंथन

पटना (आससे)। भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि की भावी व्यवस्था और बिहार की जल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को सेमिनार होगा। जल संसाधन विभाग के तत्वावधान में होनेवाले इस सेमिनार में विशेषज्ञ गंगा जल संधि के तकनीकी एवं नीतिगत पहलुओं, राज्य की वर्तमान और भविष्य की जल आवश्यकताओं, गाद जमाव, बाढ़ प्रबंधन तथा जल की दीर्घकालिक उपलब्धता पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच १२ दिसंबर, १९९६ को ३० वर्षों के लिए हस्तारित गंगा जल संधि की अवधि ११ दिसबंर को समाप्त हो रही है। संधि के तहत फरक्का बैराज से नीचे की ओर जल बंटवारे की व्यवस्था है। बिहार की बढ़ती जल जरूरतों को देखते हुए संधि की भावी व्यवस्था में राज्य के हतों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने २०५१ तक की अनुमोदित जल आवश्यकता का वैज्ञानिक आकलन कराया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार जनवरी से मई तक गैर मॉनसून अवधि में बिहार को न्यूनतम लगभग १० हजार क्यूसेक पानी की आवश्यकता है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

बिहार म्यूजियम को...

के बीच बिहार म्यूजियम ने 9वां स्थान हासिल किया है. रैंकिंग में एशिया के 10 म्यूजियम शामिल हैं, जिनमें जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और भारत के संस्थान हैं. इनमें बिहार म्यूजियम सबसे ऊपर रहा। पटना में स्थित बिहार म्यूजियम एक आधुनिक राज्य संग्रहालय है, जहां बिहार के इतिहास को पाषाण काल से आधुनिक दौर तक दिखाया गया है. यहां प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, पांडुलिपियां, पुरातात्विक अवशेष और लोककला से जुड़ी वस्तुएं रखी गई हैं. म्यूजियम की दीर्घाओं को अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ताकि पर्यटक बिहार के इतिहास और सांस्कृतिक विकास को समझ सकें. यहां बच्चों के लिए अलग दीर्घा, प्राचीन मूर्तियों की प्रदर्शनी और क्षेत्रीय लोककला का संग्रह भी है. इसके अलावा, इतिहास पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई जाती है. म्यूजियम का खुला परिसर, हरे-भरे लॉन और आकर्षक इमारत भी पर्यटकों को आकर्षित करती है।

बिहार म्यूजियम की इस उपलब्धि से पटना को सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान मिलने की उम्मीद है. बिहार अपनी प्राचीन सभ्यता, बौद्ध स्थलों, पुरातात्विक धरोहर और लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में म्यूजियम की जगह मिलने से देश-विदेश के पर्यटकों का ध्यान बिहार की ओर आकर्षित हो सकता है. इससे राज्य की ऐतिहासिक धरोहर को बढ़ावा देने और स्थानीय पर्यटन को मजबूत करने में भी मदद मिल सकती है।

बिहार में तकनीकी...

बाढ़ की निगरानी, जल प्रबंधन, कृषि नियोजन और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाया जा सकता है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्षा में लगभग 32 प्रतिशत की कमी के बावजूद बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पानी के कारण गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों के जलस्तर पर प्रभाव देखा गया। ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, जलस्तर की निरंतर निगरानी और समन्वित जल प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने गंगा के जल का वर्षभर पेयजल और सिंचाई जैसे उद्देश्यों के लिए समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी पहल करने पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए प्रयासरत है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 रुपये और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पांच रुपये की फीस की व्यवस्था युवाओं को तकनीकी शिक्षा हासिल करने का अवसर देती है।

उन्होंने ऐतिहासिक विरासत से प्रेरित 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना का उल्लेख करते हुए नियोजित शहरी विकास में आधुनिक तकनीक की उपयोगिता पर भी बल दिया। उन्होंने संबंधित विभागों और तकनीकी संस्थानों से आपसी समन्वय बढ़ाने तथा नवाचारों को जनहित से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी सहित अन्य अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे।

सी के अनिल बने...

बनाया गया है। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी को अगले आदेश तक कृषि विभाग के कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री चौधरी पूर्व से ही बिपार्ड के महानिदेशक तथा बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक के अतिरिक्त प्रभार में भी कार्यरत हैं। प्रशासनिक फेरबदल के क्रम में गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को वर्तमान में धारित सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पाण्डेय को अगले आदेश तक कृषि विभाग के अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

बिहार में 15 हजार...

दिया गया। उन्होंने परिवहन विभाग को लाइसेंस निलंबन के लिए पुलिस के स्तर से प्राप्त अनुशंसाओं पर 15 दिनों के भीतर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध अभियान तेज करने का भी निर्देश दिया। जेब्रा क्रॉसिंग, रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर एवं रोड साइनेज जैसे सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा हुई।

अलकतरा घोटाला में...

उसे दोषी करार देते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत 1 वर्ष 4 महीने 18 दिन के कारावास की सजा के साथ 29 लाख रूपयों का जुर्माना भी किया। कारावास की सजा जेल में बिताई गई अवधि में समायोजित की गई जबकि दोषी ने 29 लाख रुपए का जुर्माना अदालत में जमा कर दिया। जिसके बाद उसका मुकदमा निष्पादित कर दिया गया । दूसरी ओर इसी मुकदमे के दो अन्य आरोपितों तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन और तत्कालीन डायरेक्टर परचेज एंड ट्रांसपोर्ट केदार पासवान के खिलाफ मामले में अंतिम बहस जारी है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश दुबे ने बताया कि मामला वर्ष 1994 का था। आरोप के अनुसार एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी ट्रांसपोर्टर दूधेश्वर नाथ सिंह ने बरौनी रिफाइनरी से 494.68 मेट्रिक अलकतरा का उठाव किया था जिसे जमुई पथ निर्माण प्रमंडल में पहुंचाना थे लेकिन उक्त अलकतरा गायब कर दिया गया जिसकी कीमत 28 लाख 43 हजार 555 रुपए थी। मामले की मूल प्राथमिकी बरौनी थाने में वर्ष 1996 में दर्ज की गई थी। बाद में सीबीआई ने इस मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश से अपने हाथ में ली थी और आरसी 9(ए) 1997 के रूप में अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोपितों में तिरुपति ट्रांसपोर्ट के मालिक दूधेश्वर नाथ सिंह, तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन, तत्कालीन डायरेक्टर परचेज एंड ट्रांसपोर्ट केदार पासवान, तत्कालीन इंजीनियर इन चीफ डी एन बैठा, तत्कालीन उपनिदेशक मुजतबा अहमद और मदन मोहन प्रसाद शामिल थे । मामले की सुनवाई के दौरान डी एन बैठा, मुजतबा अहमद और मदन मोहन प्रसाद की मृत्यु हो गई । वर्तमान में अब मुकदमा मोहम्मद इलियास हुसैन और केदार पासवान के खिलाफ अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।

टेंडर घोटाले में...

पक्ष जानने के साथ-साथ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भी पूछताछ की गई। इससे एक दिन पहले बुधवार को ईडी ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष आईएएस धर्मेंद्र कुमार से करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक, उनसे सुबह करीब 11 बजे से शाम 6 बजे तक सवाल-जवाब किए गए। इस दौरान जांच अधिकारियों ने रिशुश्री के साथ हुई चैट के कुछ अंश और अन्य साक्ष्य दिखाकर 40 से अधिक सवाल पूछे।

धर्मेंद्र कुमार से पूछताछ के दौरान उनकी विदेश यात्रा से जुड़े तथ्यों पर भी सवाल उठाए गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र कुमार और उनकी पत्नी ने 16 जुलाई से 26 जुलाई 2025 के बीच यूरोप की यात्रा की थी। उस समय वह बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे।ईडी की ओर से अदालत में पेश रिपोर्ट के अनुसार, ठेकेदार रिशु श्री ने धर्मेंद्र कुमार और उनकी पत्नी की यूरोप यात्रा के दौरान 10,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि की व्यवस्था की थी, हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि यह पूरी राशि नकद दी गई थी या इसके कुछ हिस्से की व्यवस्था किसी अन्य माध्यम से की गई थी।जांच एजेंसी इस मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अधिकारियों के साथ कथित संपर्कों की पड़ताल कर रही है। पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

टेंडर घोटाले की जांच अब बिहार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गई है। ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए छह आईएएस अधिकारियों को समन भेजा है। एजेंसी इन अधिकारियों से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है, ताकि कथित टेंडर घोटाले में उनकी भूमिका और अन्य संबंधित पहलुओं को समझा जा सके। संतोष कुमार मल्ल से पहले ईडी आईएएस धर्मेंद्र कुमार, आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा और आईएएस सुनील यादव से पूछताछ कर चुकी है। वहीं, योगेश सागर ने पूछताछ के लिए पेश होने की तारीख आगे बढ़वा ली है। आईएएस आनंद किशोर को 30 अक्टूबर को ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए तलब किया गया है।

सूबे के मॉडल स्कूलों...

इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। विभाग द्वारा जारी पत्र में मॉडल स्कूलों में पुलिस के ठहरने की व्यवस्था यथासंभव नहीं करने को कहा गया है। जिन विद्यालयों में लिपिक और परिचारी पदस्थापित नहीं हैं, वहां नजदीकी विद्यालयों से लिपिक और परिचारी प्रतिनियुक्त किया जाए। इन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएं। जरूरत पड़ने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी वैकल्पिक परीक्षा केंद्रों की अनुशंसा करेंगे।विद्यालयों में चेतना सत्र का नियमित और बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान वाद्य यंत्रों का उचित उपयोग भी हो। इसकी नियमित निगरानी के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से एक पदाधिकारी नामित करेंगे। इसके साथ ही, कक्षा नौवीं में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को इन निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

बीपीएससी ने मेडिकल...

ली है, इसलिए उक्त सभी विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, आयोग ने अपने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि यह बहाली पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग से संशोधित अधियाचना प्राप्त होने के आलोक में अब नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।जल्द ही आयोग द्वारा संशोधित रिक्तियों के साथ ताजा विज्ञापन जारी किया जाएगा।

दरभंगा स्नातक सीट...

बावजूद जीत-हार का फैसला नहीं हो पा रहा था। इस कारण पूरे राज्य की राजनीतिक निगाहें दरभंगा सीट के परिणाम पर टिकी थीं। मतगणना के 10वें राउंड में भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार, राजद के अनिल कुमार झा से करीब 1,500 मतों से आगे चल रहे थे। हालांकि, जीत के लिए निर्धारित 31,911 मतों का आंकड़ा किसी प्रत्याशी के हासिल नहीं करने के कारण आगे की गिनती जारी रखी गई। गुरुवार को 32 प्रत्याशियों को छांटने के बाद शेष प्रत्याशियों के मतों की गिनती की प्रक्रिया आगे बढ़ी। एक चरण में कांग्रेस प्रत्याशी रजनीकांत पाठक के मतों की गिनती पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी 1,046 मतों से आगे थे। इसके बावजूद अंतिम परिणाम राजद के पक्ष में रहा और अनिल कुमार झा विजयी घोषित किए गए। राजद की इस जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया।

भ्रष्टाचार के आरोप...

जयकिशोर साह ने लगाया था. साथ ही आर्थिक अपराध इकाई प्रतिनियुक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जांच रिपोर्ट दी गयी थी. इसके आधार पर संदीप कुमार के द्वारा अपनी सास रीना कुमारी के नाम से जमीन रिश्वत में लेकर, लादावी/बाजदावी से संबंधित एकरारनाम